



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11122020-223649  
CG-DL-E-11122020-223649

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3950]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 10, 2020/अग्रहायण 19, 1942

No. 3950]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 10, 2020/AGRAHAYANA 19, 1942

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2020

**का.आ. 4492(अ).—** केंद्रीय सरकार द्वारा मालदीव गणराज्य की सरकार के साथ मालदीव गणराज्य में किसी व्यक्ति पर दांडिक मामलों के संबंध में समन या तलाशी वारंट की तामील या निष्पादन करने के लिए हैं ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 105 की उपधारा (1) के खंड (ii) के अनुसरण में यह विनिर्दिष्ट करती है कि –

(क) किसी अभियुक्त व्यक्ति को समन, या

(ख) किसी व्यक्ति को उसे हाजिर होने और दस्तावेजों या अन्य चीज को प्रस्तुत करने या उसे हाजिर करने के लिए समन, या

(ग) तलाशी वारंट

भारत में किसी न्यायालय द्वारा दो प्रतियों में मालदीव गणराज्य में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिकारिता रखने वाले उस देश के किसी न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को केंद्रीय प्राधिकारी द्वारा अर्थात् मालदीव गणराज्य में सरकार के न्याय मंत्रालय से उसमें नामित व्यक्ति पर ऐसे समन की तामील या ऐसे तलाशी वारंट के निष्पादन के लिए जारी किया जा सकेगा । भारत में संबंधित न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट से समन जारी करते समय गृह मंत्रालय के पत्र सं. 25016/52/2019-विधिक प्रकोष्ठ, तारीख 04 दिसम्बर, 2019 में अंतर्विष्ट व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन करना अपेक्षित होगा ।

2. केंद्रीय सरकार यह और निदेश देती है कि ऐसा समन या वारंट मालदीव गणराज्य की सरकार के महाभियोजक कार्यालय को पारेषित करने के लिए आई एस-2 प्रभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को भेजा जाएगा।

[फा.सं. 12015/1/2020-आईसी- 3]

सहेली घोष रॉय, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2020

**S.O. 4492(E).**— Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Government of the Republic of Maldives for service or execution of summons or search warrant in relation to criminal matters, on any person in Republic of Maldives;

Now, therefore, in pursuance of clause (ii) of sub-section (1) of section 105 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby specifies that –

- (a) a summons to an accused person, or
- (b) a summons to any person requiring him to attend and produce a document or other thing, or to produce it, or
- (c) a search-warrant

may be issued by a Court in India in duplicate, to the Court, Judge or Magistrate in the Government of the Republic of Maldives, having authority under the law for the time being in force in that country, through the Competent Authority, that is, the Prosecutor General's Office of the Government of the Republic of Maldives to serve such summons or execute such warrant on the person or place named therein. The concerned Court, Judge or Magistrate in India, while issuing summons are required to comply with the comprehensive guidelines contained in Ministry of Home Affairs issued vide letter No.25016/52/2019-LC dated the 4<sup>th</sup> December 2019.

2. The Central Government further directs that such summons or warrant shall be sent to the IS-II Division of the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi, for transmission to the Competent Authority, that is, the Prosecutor General's Office of the Government of Republic of Maldives.

[F.No.12015/1/2020-IC-III]

SAHELI GHOSH ROY, Jt. Secy.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2020

**का.आ. 4493(अ).**— केंद्रीय सरकार द्वारा मालदीव गणराज्य की सरकार के साथ मालदीव गणराज्य में किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामलों के संबंध में, समन की तामील या तलाशी वारंट का तामील या निष्पादन करने के लिए हैं ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 105 की उपधारा (2) के परंतुक के अनुसरण में यह विनिर्दिष्ट करती है कि जब भारत का कोई न्यायालय किसी ऐसे समन या तलाशी वारंट का निष्पादन करता है जो मालदीव गणराज्य की सरकार में उस देश में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट से प्राप्त हुआ है तो ऐसे मामलों में प्रस्तुत दस्तावेजों या चीजों या तलाशी में पाई गई वस्तुओं को ऐसे समन या तलाशी वारंट जारी करने वाले न्यायालय को पारेषित करने के लिए आई एस-2 प्रभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को भेजा जाएगा।

[फा.सं. 12015/1/2020-आईसी- 3]

सहेली घोष रॉय, संयुक्त सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th December, 2020

**S.O. 4493(E).**— Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Government of the Republic of Maldives for services or execution of summons or search warrant in relation to criminal matters on any person in Republic of Maldives;

Now, therefore, in pursuance of the proviso to sub-section (2) of section 105 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby specifies that in case where a Court in India executes any summons or search warrant received from a Court, Judge or Magistrate in the Government of the Republic of Maldives, having authority under the law for the time being in force in that country, the documents or things produced or things found in the search shall be forwarded to the Court issuing such summons or search-warrant through IS-II Division of the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi.

[F.No.12015/1/2020-IC-III]

SAHELI GHOSH ROY, Jt. Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2020

**का.आ. 4494(अ).**— केंद्रीय सरकार द्वारा मालदीव गणराज्य की सरकार के साथ मालदीव गणराज्य में किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामलों के संबंध में, समन की तामील या तलाशी वारंट का तामील या निष्पादन करने के लिए हैं ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 105ख की उपधारा (2) के अनुसरण में यह विनिर्दिष्ट करती है कि किसी आपराधिक मामले में किसी अन्वेषण या जांच के अनुक्रम में किसी व्यक्ति की उपस्थिति के लिए समन जिनकी मालदीव गणराज्य में किसी स्थान पर तामील या निष्पादन किया जाना है को इससे उपाबद्ध प्ररूप में जारी किया जाएगा और ऐसे समनों को गृह मंत्रालय के पत्र सं. 25016/52/2019-विधिक प्रकोष्ठ, तारीख 04 दिसम्बर, 2019 में अंतर्विष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार आई एस-2 प्रभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को केन्द्रीय प्राधिकारी अर्थात् मालदीव गणराज्य सरकार के महाभियोजक कार्यालय को पारेषित किए जाने के लिए भेजा जाएगा।

**प्ररूप****साक्षियों को समन**

(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 105ख की उपधारा (2) देखिए)

सेवा में

मालदीव गणराज्य में न्यायालय या न्यायाधीश /मजिस्ट्रेट\_\_\_\_\_

(द्वारा केंद्रीय प्राधिकारी अर्थात् मालदीव गणराज्य की सरकार का महाभियोजक कार्यालय)

मेरे समक्ष यह आवेदन किया गया है कि (अभियुक्त का नाम) (पता) (या जो उस बात के लिए संदिग्ध है) ने अपराध (समय और स्थल के साथ अपराध का संक्षिप्त विवरण) कारित किया है और मुझे यह प्रतीत होता है कि आप अभियोजन के लिए तात्विक साक्ष्य दे सकते हैं या कोई दस्तावेज या अन्य चीज प्रस्तुत कर सकते हैं;

इसलिए आप ऐसे दस्तावेजों या चीज को प्रस्तुत करने के लिए या इसका साक्ष्य देने के लिए कि आप उक्त आवेदन के विषय के बारे में क्या जानते हैं। न्यायालय के समक्ष.....दिन को .....प्रातः/अपराहन में हाजिर हों, और उसके पश्चात् न्यायालय के आदेश के बिना न जाएं और आपको इसके द्वारा यह चेतावनी दी जाती है कि यदि आप उक्त

तारीख को न्यायसंगत हेतुक के बिना हाजिर नहीं होंगे या उससे इंकार करेंगे, तो आपको हाजिर होने से बाध्य करने के लिए एक वारंट जारी किया जाएगा।

यह मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा के अधीन तारीख.....20..... को प्रदत्त किया गया है।

न्यायालय की मुद्रा

न्यायालय /मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर

[फा.सं. 12015/1/2020-आईसी- 3]

सहेली घोष रॉय, संयुक्त सचिव

### NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2020

**S.O. 4494(E).**— Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Government of the Republic of Maldives, for services or execution of summons in relation to criminal matters on any person in the Republic of Maldives;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (2) of section 105B of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby specifies that a summons for attendance of a person in the course of an investigation or inquiry in any criminal case, to be served or executed in any place in the Republic of Maldives, shall be issued in the form annexed hereto, and such summons shall be sent to IS-II Division of the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi, for transmission to the Competent Authority, that is, the Prosecutor General's Office or of the Government of the Republic of Maldives as per the guidelines contained in Ministry of Home Affairs issued vide letter No.25016/52/2019-LC dated the 4th December 2019.

### FORM

#### SUMMONS TO WITNESS

[See sub-section (2) of section 105B of the Code of Criminal Procedure, 1973]

To

The Court or Judge/Magistrate in the Republic of Maldives -----

(Through the Competent Authority, that is, the Prosecutor General's Office of the Government of the Republic of Maldives.)

Whereas an application has been made before me that (Name of the accused) of (address) has (or is suspected to have) committed the offence of (state the offence concisely with time and place) and it appears to me that you are likely to give material evidence or to produce any document or other thing for the prosecution;

You are hereby summoned to appear before the Court on the -----day of-----at ----- A.M./P.M. to produce such document or thing or to testify what you know concerning the matter of the said application, and not to depart then without the order of the Court, and you are hereby warned that, if you shall without just cause neglect or refuse to appear on the said date, a warrant will be issued to compel your attendance.

Given under my hand and the seal of the Court this -----day of -----20 .....

Seal of the Court

Signature of the

Judge/Magistrate

[F.No.12015/1/2020-IC-III]

SAHELI GHOSH ROY, Jt. Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2020

**का.आ. 4495(अ).—** केंद्रीय सरकार द्वारा मालदीव गणराज्य की सरकार के साथ भारत के न्यायालयों में आपराधिक मामलों के संबंध में मालदीव गणराज्य में निवास कर रहे साक्षियों का साक्ष्य लेने के लिए है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 285 की उपधारा (3) के अनुसरण में यह विनिर्दिष्ट करती है कि -

(क) मालदीव गणराज्य में साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन भारत के न्यायालयों द्वारा इससे उपाबद्ध प्ररूप में, मालदीव गणराज्य के किसी सक्षम दंड न्यायालय को जिसे मालदीव गणराज्य में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन प्राधिकार प्राप्त है, जारी किया जाएगा; और

(ख) ऐसा कमीशन आई एस-2 प्रभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को मालदीव गणराज्य की सरकार के महाभियोजक कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी को पारेषण के लिए है।

**प्ररूप**

भारत से बाहर साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन

(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 285 की उपधारा (3) देखिए)

सेवा में

न्यायालय.....

.....

(द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली)

मुझे यह प्रतीत होता है कि मामला संख्या .....बनाम. .... न्यायालय..... में..... का न्याय के उद्देश्य के लिए साक्ष्य आवश्यक है और ऐसा साक्षी आपकी स्थानीय अधिकारिता की सीमाओं के भीतर निवास कर रहा है/रही है, और उसकी हाजिरी को अयुक्तियुक्त विलंब, व्यय या असुविधा के बिना उपाप्त नहीं किया जा सकता है, मैं..... इसके द्वारा यह अनुरोध करता हूं कि आप उपरोक्त कारणों से और उक्त न्यायालय की सहायता के लिए उक्त साक्षी का ऐसे समय और स्थान पर जो आप नियत करें, हाजिर होने के लिए समन करें और ऐसे साक्षियों की परीक्षा उन परिप्रश्नों (मौखिक परीक्षा के लिए) के आधार पर करवाएं जो इस कमीशन के साथ भेजे जा रहे हैं;

कार्यवाही का कोई पक्षकार आपके समक्ष अपने काउंसेल या अभिकर्ता द्वारा या यदि अभिरक्षा में नहीं है तो स्वयं हाजिर हो सकेगा और उक्त साक्षी की (यथास्थिति) परीक्षा, प्रतिपरीक्षा या पुनःपरीक्षा कर सकेगा;

और, मैं, आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आप उक्त साक्षी के उत्तर लेखबद्ध करवाएं और उन सभी बहियों, पत्रों, कागजों और दस्तावेजों को पहचान के लिए सम्यक रूप से चिन्हित कराएं जो ऐसी परीक्षा के दौरान पेश किए जाएं, और आपसे यह भी अनुरोध करता हूं कि आप ऐसी परीक्षा को अपनी सरकारी मुद्रा और अपने हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित करें और उसे इस कमीशन के साथ अद्योहस्ताक्षरी को गृह मंत्रालय (आई एस-2 खंड), भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा भेजें।

यह मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा के अधीन तारीख.....20..... को प्रदत्त किया गया।

न्यायालय की मुद्रा

न्यायालय/मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर

[फा.सं. 12015/1/2020-आईसी- 3]

सहेली घोष राँय, संयुक्त सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th December, 2020

**S.O.4495(E).**— Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Government of the Republic of Maldives for taking the evidence of witnesses residing in the Republic of Maldives in relation to criminal matters in Courts in India;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (3) of section 285 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby specifies that -

- (a) commission for examination of witnesses in the Republic of Maldives shall be issued by the Courts in India in the Form annexed hereto, to any competent criminal court of Republic of Maldives having authority under the law for the time being in force in the Republic of Maldives; and
- (b) such Commission shall be sent to IS-II Division of the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi for transmission to the Competent Authority, that is, the Prosecutor General's Office of the Government of the Republic of Maldives.

**FORM****COMMISSION TO EXAMINE WITNESS OUTSIDE INDIA**

[See sub-section (3) of section 285 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)]

IN THE COURT OF-----  
-----

To  
-----

(Through the Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi.)

Whereas it appears to me that the evidence of ----- is necessary for the ends of justice in case No. -----, Vs.-----in the Court of ----- and that such witness is residing within the local limits of your jurisdiction and his/her attendance cannot be procured without unreasonable delay, expense or inconvenience, I, ----- have the honour to request and do hereby request that for the reasons aforesaid and for the assistance of the said Court, you will be pleased to summon the said witness to attend at such time and place as you shall appoint and that you will cause such witness to be examined upon the interrogatories which accompany this Commission (for viva voce);

Any party to the proceeding may appear before you by his/her Counsel or agent or, if not in custody, in person, and may examine, cross-examine or re-examine (as the case may be) the said witness;

And, I, further have the honour to request that you will be pleased to cause the answers of the said witness to be reduced into writing and all books, letters, papers and documents produced upon such examination to be duly marked for identification and that you will be further pleased to authenticate such examination by your official seal and signature and to return the same together with this Commission to the undersigned through IS II Division of the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi.

Given under my hand and the seal of the Court this----- day of-----20.....

Seal of the Court

Signature of the  
Judge/Magistrate

[F. No. 12015/1/2020-IC-III]  
SAHELI GHOSH ROY, Jt. Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2020

**का.आ. 4496(अ).—** केंद्रीय सरकार द्वारा मालदीव गणराज्य की सरकार के साथ मालदीव गणराज्य में किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामलों के संबंध में, समन की तामील या तलाशी वारंट का तामील या निष्पादन करने के लिए हैं ;

अतः केंद्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 290 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अनुसरण में मालदीव गणराज्य में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले ऐसे सभी न्यायालयों, न्यायाधीशों या मजिस्ट्रेटों को जिन्हें मालदीव गणराज्य में तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन प्राधिकार प्राप्त हैं, ऐसे न्यायालयों के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिनके द्वारा भारत में निवास कर रहे साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी किया जा सकेगा।

[फा.सं. 12015/1/2020-आईसी- 3]

सहेली घोष रॉय, संयुक्त सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th December, 2020

**S.O. 4496(E).—** Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Government of the Republic of Maldives for service or execution of summons or warrant in relation to criminal matters on any person in the Republic of Maldives;

Now, therefore, in pursuance of clause (b) of sub-section (2) of section 290 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby specifies that all Courts, Judges or Magistrates exercising jurisdiction in the Republic of Maldives having authority under the law in force in the Republic of Maldives as the Courts by which the Commission for the examination of witnesses residing in India may be issued.

[F.No.12015/1/2020-IC-III]

SAHELI GHOSH ROY, Jt. Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2020

**का.आ. 4497(अ).—** केंद्रीय सरकार द्वारा मालदीव गणराज्य की सरकार के साथ मालदीव गणराज्य में किसी व्यक्ति पर आपराधिक मामलों के संबंध में, समन की तामील या तलाशी वारंट का तामील या निष्पादन करने के लिए हैं ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 105ठ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त संहिता के अध्याय 7क के उपबंध मालदीव गणराज्य के संबंध में बिना किसी शर्त, अपवाद या प्रतिबंध के इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

[फा.सं. 12015/1/2020-आईसी- 3]

सहेली घोष रॉय, संयुक्त सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th December, 2020

**S.O. 4497(E).**—Whereas arrangements have been made by the Central Government with the Government of the Republic of Maldives for service or execution of summons or warrant in relation to criminal matters on any person in the Republic of Maldives;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 105 L of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the Central Government hereby directs that the provisions of Chapter VIIA of the said Code shall apply without any condition, exception or qualification in relation to Republic of Maldives with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F.No.12015/1/2020-IC-III]

SAHELI GHOSH ROY, Jt. Secy.